

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1939
दिनांक 19.12.2022 को उत्तर के लिए
जलवायु परिवर्तन निष्पादन सूचकांक

1939. श्री सुधीर गुप्ता:

श्री प्रतापराव जाधव:

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

श्री बिद्युत बरन महतो:

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या जलवायु परिवर्तन निष्पादन सूचकांक (सीसीपीआई 2023) के आधार पर भारत विश्व के शीर्ष 5 देशों और जी-20 देशों में सर्वश्रेष्ठ देशों में शामिल है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या भारत ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और ऊर्जा उपयोग की श्रेणी में उच्च रेटिंग और जलवायु नीति तथा नवीकरणीय ऊर्जा में मध्यम रेटिंग अर्जित की है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा पर्यावरणीय निष्पादन सूचकांक के कारकों में सुधार लाने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;
- (घ) सरकार द्वारा पर्यावरणीय संवहनीयता को बढ़ावा देने के लिए चलाए गए जागरूकता कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है, और
- (ङ) सरकार द्वारा देश में जलवायु परिवर्तन सूचकांक में सुधार के लिए उठाए गए अन्य कदमों और इस दिशा में किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (ङ) जलवायु परिवर्तन निष्पादन सूचकांक 2023 रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई थी तथा भारत ने उसके सूचकांक में 8वां स्थान हासिल किया जो कि पिछले संस्करण से 2 स्थान ऊपर है। चूंकि सभी सूचकांक श्रेणियों में कोई भी देश इतना मजबूत नहीं था कि समग्र रूप से बहुत उच्च रेटिंग प्राप्त कर सके, इसलिए शीर्ष तीनों स्थान यानी 1-3 स्थान खाली हैं। इसके बाद भी, भारत शीर्ष 5 देशों में शामिल है। भारत (8वां), यूनाइटेड किंगडम (11वां), और जर्मनी (16) सहित केवल तीन जी-20 देश सीसीपीआई 2023 में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों में शामिल हैं। इस प्रकार जी 20 देशों में भारत की स्थिति सर्वश्रेष्ठ है।

सीसीपीआई के विभिन्न घटकों में भारत की रेटिंग इस प्रकार है-

घटक	रेटिंग
जीएचजी उत्सर्जन	उच्च
नवीकरणीय ऊर्जा	मध्यम
ऊर्जा उपयोग	उच्च
जलवायु नीति	मध्यम

सरकार ने हाल ही में पेरिस समझौते के तहत यूएनएफसीसीसी को भारत द्वारा प्रस्तुत किए गए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों (एनडीसी) को अद्यतन किया है। इनमें वर्ष 2030 तक प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और हरित जलवायु निधि (जीसीएफ) सहित कम लागत वाले अंतरराष्ट्रीय वित्त की मदद से अपनी जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तर से 45 प्रतिशत तक कम करना; वर्ष 2030 तक गैर-जीवश्म ईंधन-आधारित ऊर्जा संसाधनों से संस्थापित क्षमता की लगभग 50 प्रतिशत संचयी विद्युत प्राप्त करना, और वर्ष 2030 तक अतिरिक्त वन और वनावरण के माध्यम से CO₂ समतुल्य का 2.5 से 3 बिलियन टन के अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण करना शामिल है। इसके अलावा, भारत ने भी पक्षकारों के 27वें सम्मेलन (सीओपी 27) के दौरान जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र कार्यवाहक सम्मेलन (यूएनएफसीसीसी) को अपनी दीर्घ-कालिक निम्न उत्सर्जन विकास कार्यनीति विकसित की है।

सरकार ने विशिष्ट ऊर्जा खपत (एसईसी) अर्थात् ऊर्जा गहन क्षेत्रों में विनिर्दिष्ट उपभोक्ताओं (डीसी) के लिए उत्पादन की प्रति यूनिट ऊर्जा के उपयोग को कम करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार भी शुरू किया है। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा शुरू की गई उजाला योजना से 36.86 करोड़ एलईडी बल्बों का वितरण हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष 47,876 मिलियन किलोवाट घण्टे की बिजली बचत हुई, अधिकतम मांग में 9,585 मेगावाट की कमी आई है और 30 जून 2022 तक सालाना 38.77 मिलियन टन CO₂ उत्सर्जन में कमी आई है। इसके अलावा, सरकार ने वर्ष 2030 तक नवीकरणीय खरीद दायित्वों (आरपीओ) के लिए प्रक्षेप पथ घोषित किया है और देश में इलेक्ट्रिक वाहनों और चार्जिंग बुनियादी ढांचे के निर्माण को बढ़ावा दे रही है।

पर्यावरणीय मुद्दों पर छात्रों को शिक्षित करने और जागरूकता बढ़ाने हेतु विद्यालयों और कॉलेजों में ईको-क्लब बनाए गए हैं। ईको-क्लब के अधीन गतिविधियों में वृक्षारोपण अभियान, स्वच्छता अभियान, पर्यावरण के प्रति हरित प्रतिज्ञाएं शामिल हैं। ईआईएसीपी (पर्यावरणीय जानकारी, जागरूकता और क्षमता निर्माण) के तहत संसाधन केंद्र भी पर्यावरण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु जागरूकता उत्पन्न करने और उससे संबंधित कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए 'स्वच्छ वायु-दिवस ('स्वच्छ वायु नील गगन') के रूप में नीले आसमान के लिए तीसरा अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस का भी आयोजन किया था। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत जागरूकता सह समीक्षा कार्यशाला भी आयोजित की गई थी।
